भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4178

उत्तर देने की तारीख-01/04/2026

आईआईटी और आईआईएम में अवसंरचना संबंधी और शैक्षणिक मानक

4178 **डा. अजित माधवराव गोपछड़े:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) में स्वीकृत और कार्यरत शिक्षण संकाय, शैक्षणिक और शिक्षकेतर स्टाफ की संस्थान-वार वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनमें से प्रत्येक संस्थान में मुख्य शैक्षणिक, अनुसंधान, आवासीय और प्रशासनिक अवसंरचना की उपलब्धता और पर्याप्तता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने संकाय की कमी को दूर करने, अवसंरचना में वृद्धि करने और शैक्षणिक तथा अनुसंधान मानकों को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से नए आईआईटी और आईआईएम में, लक्षित अंतःक्षेप शुरू किए हैं या शुरू करने का विचार रखती है ताकि पुराने और सुस्थापित संस्थानों के साथ कार्यात्मक, शैक्षणिक और प्रतिष्ठित समानता सुनिश्चित की जा सके और यदि हां, तो समय-सीमा और परिणामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान संसद के संबंधित केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक स्वायत्त संगठन हैं तथा इसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों और संविधियों के उपबंधों द्वारा शासित होते हैं। बजट भाषण वर्ष 2025-26 में, अतिरिक्त 6,500 छात्रों के लिए शिक्षा की सुविधा हेतु वर्ष 2014 के बाद शुरू किए गए पांच आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा सृजित करने की घोषणा की गई है। तदनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई, 2025 में आयोजित अपनी बैठक में 11,828.79 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू और कश्मीर (आईआईटी जम्मू) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) में स्थापित पांच नए आईआईटी के अनुसंधान पार्क के निर्माण सहित शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे की क्षमता के विस्तार को मंजूरी दी है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) के माध्यम से शैक्षणिक और छात्रावास के बुनियादी ढांचे के विस्तार और आईआईटी जोधपुर, आईआईटी पटना और आईआईटी इंदौर के लिए अनुसंधान पार्क के विकास के लिए कुल 1,942 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इन अनुसंधान पार्कों का उद्देश्य शीर्ष रेटेड उद्योगों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना, उद्यमिता और छात्र इनक्यूबेशन का समर्थन करना, अकादमिक-उद्योग संबंधों को मजबूत बनाना, उद्योग के लिए शैक्षणिक सामग्री की पहुंच बढ़ाना और उद्योगों को प्रबल साझेदारी के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रमों में योगदान

करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा, इन संस्थानों के आसपास अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए आठ आईआईटी और आईआईएससी बेंगलुरु में अनुसंधान पार्क स्थापित किए गए हैं। सरकार ने उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) के माध्यम से अन्य पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसंधान पार्कों की स्थापना का भी अनुमोदन किया है।

सरकार ने दिनांक 3 नवंबर, 2025 को अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना भी शुरू की है, जो 1 लाख करोड़ रुपये की पहल है, जो भारत के अनुसंधान और विकास परिदृश्य को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है।

तीसरी पीढ़ी के आईआईएम (अर्थात 2015-16 के बाद स्थापित) सहित सभी 21 आईआईएम अब अपने स्थायी परिसर से काम कर रहे हैं अर्थात वे मुख्य बुनियादी ढांचे के मामले में आत्मनिर्भर हैं। आईआईएम अधिनियम, 2017 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक आईआईएम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स संस्थान का प्रमुख कार्यकारी निकाय है। परिसर विकास के लिए प्रस्ताव परिसर विकास समिति/भवन एवं निर्माण समिति द्वारा शासी बोर्ड क समक्ष रखे जाते हैं। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, संस्थान, उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) से प्राप्त ऋण के माध्यम से काम को निष्पादित करता है।

भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए, सरकार ने वर्ष 2018-19 में 1650 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो (पीएमआरएफ) योजना शुरू की। यह योजना, जिसमें फेलोशिप और अनुसंधान अनुदान शामिल हैं, बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए शुरू की गई थी। पीएमआरएफ के तहत 3688 स्कॉलर्स को एडमिशन दिया गया है। पीएमआरएफ के पहले चरण से अनुसंधान के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और इस प्रकार, बजट 2025-26 में पीएमआरएफ के तहत बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप की घोषणा की गई है। आईआईटी और आईआईएम सहित उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 1 जनवरी 2025 स एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) शुरू की है।

सभी आईआईटी और आईआईएम को मिशन मोड भर्ती के तहत रिक्त संकाय पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इस पहल के हिस्से के रूप में, सितंबर 2022 से जनवरी 2026 की अवधि के दौरान, आईआईटी ने 3,285 संकाय सदस्यों की नियुक्ति की है, जबकि आईआईएम ने 537 संकाय सदस्यों की नियुक्ति की है।

*****